



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2003/श्रावण 15, 1925

No. 709]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2003/SRAVANA 15, 1925

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2003

का.आ. 908(अ).—केन्द्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 102 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य सरकारों द्वारा सम्यक रूप से तैयार और अनुमोदित, तथा अनुमोदन हेतु उक्त राज्य सरकारों द्वारा उसकी उप-धारा (1) के अंतर्गत उसे अग्रेषित, उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्य वक्फ बोर्डों के विभाजन की स्कीम को अनुमोदित करती है तथा निम्नलिखित आदेश करते हुए इस प्रकार अनुमोदित स्कीम को प्रभावी करती है, अर्थात् :-

- (क) वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड विघटित कर दिए जाएंगे और दोनों उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल दोनों राज्य सरकार वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 और 14 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार स्वयं अपने राज्य वक्फ बोर्ड गठित करेंगी तथा पुनर्गठित बोर्डों का संबंधित उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में आने वाले क्षेत्रों पर अधिकारिता होगी;
- (ख) उत्तरांचल राज्य वक्फ बोर्ड का उत्तरांचल राज्य के भीतर आने वाली 2032 सुन्नी और 21 शिया वक्फ संपत्तियों पर अधिकारिता और नियंत्रण होगा। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड का उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर आने वाली वक्फ संपत्तियों पर अधिकारिता और नियंत्रण होगा। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के वर्तमान वक्फ बोर्डों की आस्तियां, धन और दायित्व संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों की आस्तियां, धन तथा दायित्व मानी जाएंगी जिसमें वे उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन की तारीख को विद्यमान थी;

- (ग) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर और बिजनौर जिलों में आने वाली उन सुन्नी वक्फों के संबंध में जहां एक ही मुतवल्ली हो किन्तु संपत्तियां दोनों राज्यों में हों वहां स्थानीय वक्फ बोर्ड का अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाली संपत्तियों पर नियंत्रण होगा । संबंधित मुतवल्ली अपनी संबंधित अधिकारिता में आने वाली संपत्तियों के संबंध में दोनों वक्फ बोर्डों को पृथक बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 72 के अधीन 7% अंशदान एकत्र करेंगे और संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में पृथकरूप से जमा करेंगे । यदि ऐसे वक्फों की बाबत उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य वक्फ बोर्डों के पुनर्गठन के पश्चात् नए मुलवल्लियों की नियुक्ति की अपेक्षा की जाती है तो अपने संबंधित अधिकारिता में स्थित ऐसी वक्फ संपत्तियों के लिए संबंधित वक्फ बोर्डों द्वारा पृथक मुतवल्लियों की नियुक्ति की जाएगी ;
- (घ) उत्तरांचल के 13 जिलों के अधीन उत्तर प्रदेश के वर्तमान वक्फ बोर्डों में सभी पद और कर्मचारी जो उत्तरांचल के 13 जिलों और 2 मंडलों (कुमांउ और गढ़वाल) से बाहर स्थानान्तरणीय नहीं थे, उत्तरांचल राज्य वक्फ बोर्ड के पद और कर्मचारी माने जाएंगे । अन्य सभी कर्मचारियों के संबंध में, जो पूरे तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरणीय थे, दोनों राज्यों द्वारा पारस्परिक करार से नीतिगत विनिश्चय किया जाएगा;
- (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य वक्फ बोर्डों के उत्तरांचल औकफ के पुराने अतिशोध्यों सहित सभी शोध्यों की उनसे वसूली की जाएंगी तथा उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा संबंधित उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्डों को इस आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर भुगतान किया जाएगा और ऐसा नहीं करने पर उत्तरांचल राज्य सरकार तीन मास की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् एक मास के भीतर अपने संसाधनों से ऐसा भुगतान करेगी ;
- (च) उत्तर प्रदेश राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों द्वारा उत्तरांचल राज्य में आने वाली शिया और सुन्नी वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी फाइलें और दस्तावेज उत्तरांचल राज्य वक्फ बोर्ड को अंतरित किए जाएंगे, तथा उत्तरांचल वक्फ बोर्ड विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वाद और कार्यवाही के संबंध में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्डों के स्थान पर उत्तरांचल वक्फ बोर्ड के प्रतिस्थापन हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगा ;

- (छ) उत्तरांचल राज्य में आनेवाली वक्फ संपत्तियों के मुतवल्लीयों के विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित सभी फाईलें उत्तरांचल वक्फ बोर्ड को अंतरित की जाएंगी और यदि कोई ऐसा मुतवल्ली दोनों राज्यों में आने वाली वक्फ संपत्तियों की देखभाल कर रहा है तो वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 64 के अधीन ऐसे मुतवल्ली के विरुद्ध कार्रवाई उस वक्फ बोर्ड द्वारा की जाएगी जिनके अधिकारिता में वह संपत्ति जिसके संबंध में कार्यवाही लंबित है, स्थित है ;
- (ज) इस आदेश के अंतर्गत न आनेवाले सभी मामलों पर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य सरकारों द्वारा आपसी विचार-विमर्श द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और किसी विवादक पर असहमति की दशा में, उक्त राज्य सरकारों द्वारा मामले को केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय बाध्यकारी होगा ।

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 4(32)/2000-वक्फ]

सपना राय, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

**ORDER**

New Delhi, the 5th August, 2003

**S.O. 908(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 102 of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby approves the scheme of division of the existing State Wakf Boards in Uttar Pradesh, duly framed and approved by the State Governments of Uttar Pradesh and Uttaranchal and forwarded to it under sub-section (1) thereof, by the said State Governments for approval, and gives effect to the scheme so approved by making the following Order, namely:—

- (a) The existing Uttar Pradesh State Shia and Sunni Wakf Boards shall be dissolved and both the State Governments of Uttar Pradesh and Uttaranchal shall constitute their own State Wakf Boards as per the provisions contained in sections 13 and 14 of the Wakf Act, 1995 and the re-constituted Boards shall have jurisdiction over the areas falling in the respective States of Uttar Pradesh and Uttaranchal;

- (b) The State Wakf Board of Uttaranchal shall have the jurisdiction and control over 2032 Sunni and 21 Shia wakf properties falling within the State of Uttaranchal. Similarly, the State Wakf Boards of Uttar Pradesh shall have jurisdiction and control over the wakf properties falling within the State of Uttar Pradesh. Further, all other assets, moneys and liabilities of the existing Wakf Boards of Uttar Pradesh shall be deemed to be the assets, moneys and liabilities of the respective State Wakf Boards in which they existed as on the date of division of the State of Uttar Pradesh;
- (c) In respect of such Sunni wakfs falling in the districts of Bulandshahr and Bijnaur of Uttar Pradesh, as having the same Mutawalli but the properties being in both the States, the local Wakf Board shall have the control over the properties falling within its jurisdiction. The concerned Mutawallis shall submit separate budget proposals to both the Wakf Boards in respect of the properties falling in their respective jurisdiction and shall collect and deposit the 7% contribution under section 72 of the Wakf Act, 1995 with the respective State Wakf Boards separately. If new Mutawallis are required to be appointed after re-constitution of the State Wakf Boards of Uttar Pradesh and Uttaranchal in respect of such wakfs, then separate Mutawallis shall be appointed by the respective Wakf Boards in respect of properties of such wakf situated in their respective jurisdiction;
- (d) All the posts and employees in the existing Wakf Boards of Uttar Pradesh under the 13 districts of Uttaranchal that were not transferable outside the 13 districts and 2 divisions (Kumaon and Garhwal) of Uttaranchal, shall be deemed to be the posts and employees of the Wakf Board of the State of Uttaranchal. In respect of all other employees who were transferable within the entire erstwhile State of Uttar Pradesh, a policy decision shall be taken by both the States by mutual agreement;

- (e) All dues, including old overdues, of the Aukafs of Uttaranchal to the State Wakf Boards of Uttar Pradesh shall be recovered from them and paid by the State Government of Uttaranchal to the concerned Wakf Boards of Uttar Pradesh within three months from the date of this Order failing which the State Government of Uttaranchal shall make such payment from its own resources within one month after the expiry of the above period of three months;
- (f) All the files and documents pertaining to Shia and Sunni Wakf properties falling in the State of Uttaranchal shall be transferred to the State Wakf Board of Uttaranchal by the Uttar Pradesh State Shia and Sunni Wakf Boards, and the Uttaranchal Wakf Board shall take necessary action for substitution of Uttaranchal Wakf Board in place of the Uttar Pradesh Wakf Boards in respect of suits and proceedings pending in various courts;
- (g) All files pertaining to action against Mutawallis of wakf properties falling in the State of Uttaranchal shall be transferred to the Uttaranchal Wakf Board and if any such Mutawalli is looking after wakf properties falling in both States, then action against such Mutawalli under section 64 of Wakf Act, 1995 shall be taken by the Wakf Board in whose jurisdiction the property in respect of which the proceeding is pending is located;
- (h) All matters not covered by this Order shall be decided by the State Governments of Uttar Pradesh and Uttaranchal by mutual discussion and in case of disagreement on any issue, the matter shall be referred by the said State Governments to the Central Government and the decision of the Central Government shall be binding.

2. This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 4(32)/2000-Wakf]  
SWAPNA RAY, Jt. Secy.